भारत और चीन

चर्चा में क्यों ?

- 2022 में, चीन से भारत का आयात रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि चीन का निर्यात 5 वर्ष के निचले स्तर पर आ गया। इस असंतुलन ने व्यापार घाटे को और बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- चीन से आयात 2022 में रिकॉर्ड 94.7 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया। यह भारत के कुल आयात के हिस्से के रूप में 14% हो गया।
- भारत की कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2020 में लगभग 7% से घटकर 2022 में 3.4% हो गयी।
- इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारत द्वारा चीन से सबसे अधिक आयातित सामान थे। हालांकि, भारत अकेला नहीं है क्योंकि चीन से आयात पर निर्भरता भारतीय पड़ोसी देशों और अन्य ब्रिक्स देशों के बीच भी निरंतर बढ़ी है।

सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ

- यह पिछले 3 वर्षों में संयुक्त रूप से भारत द्वारा चीन को निर्यात किए गए 20 सबसे अधिक निर्यात किए गए सामानों को दर्शाता है - 2022, 2021 और 2020। इनमें से, सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ अयस्क, खनिज ईंधन , तेल और लोहा तथा इस्पात जैसी श्रेणियों से संबंधित थीं। पेट्रोलियम तेल, लौह अयस्क, और झींगा सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ थीं।

सबसे ज्यादा आयातित वस्तुएँ

- यह पिछले 3 वर्षों - 2022, 2021 और 2020 में भारत द्वारा चीन से 20 सबसे अधिक आयातित वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरण, यांत्रिक उपकरण, जैविक रसायन और उर्वरक से संबंधित थीं। लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट और टेलीफोन सेट तथा पुर्जे सबसे अधिक आयातित सामान थे।

देशवार निर्भरता

- चीन से आयात पर निर्भरता भारत के पड़ोसियों - पाकिस्तान और श्रीलंका तथा ब्रिक्स देशों अर्थात् रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में बढ़ी है। यह यू.एस. में अपरिवर्तित रहा और यू.के. में थोड़ा बढ़ा।

वस्तुओं पर निर्भरता

- लैपटॉप और सेमीकंडक्टर उपकरणों जैसे सामानों के मामले में निर्भरता अधिक बनी हुई है। लेकिन यूरिया और सेल्युलर फोन के कुछ हिस्सों में निर्भरता कम हुई, लेकिन अब यह भी निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति पर है।

स्रोत- द हिन्दू

ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा 'प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग वाले ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन' से सम्मानित किया गया है।

- भारतीय रेलवे के पर्यावरण ईमेल ने IGBC के सहयोग से ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम विकसित किया है। यह जल संरक्षण, उद्यम प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, पेट्रोलियम ईंधन का कम उपयोग तथा स्वास्थ्य और कल्याण जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को शामिल करता है।
- यह एक स्वैच्छिक और आम सहमति आधारित कार्यक्रम है।
- भारतीय रेलवे स्टेशनों में पर्यावरणीय स्थिरता को संबोधित करने के लिए यह भारत में अपनी तरह की पहली समग्र रेटिंग है।

इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGCB) के बारे में

- यह वर्ष 2001 में गठित भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) का हिस्सा है।
- परिषद सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है जिसमें नए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग कार्यक्रम, प्रमाणन सेवाएं और ग्रीन बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना शामिल है।
- परिषद ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का भी आयोजन करती है, जो हरित भवनों पर इसका वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है।

- परिषद समिति-आधारित, सदस्य-संचालित और आम सहमति-केंद्रित है। सभी हितधारक, कॉर्पोरेट, सरकार, शिक्षाविद और नोडल एजेंसियां परिषद की गतिविधियों में भाग लेते हैं।
- परिषद देश में हरित भवन अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और द्विपक्षीय बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है।

स्रोत- पीआईबी

केल्प वन

चर्चा में क्यों ?

- जर्नल नेचर में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण केल्प वन घट रहे हैं।

केल्प वनों के बारे में:

- समुद्र के पानी में कई विशाल जंगल हैं। सबसे बड़ा जंगल केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है, जिसका दायरा 5,800 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है।
- धरती के घने जंगल की तरह ही केल्प फॉरेस्ट में भी काफी खूबसूरत और लंबे-लंबे पेड़ हैं। इस जंगल में 260 फुट लंबे पेड़ हो सकते हैं।
- केल्प ठंडे, पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पनपता है।
- वे समुद्र तल से जुड़े होते हैं और अंततः पानी की सतह तक बढ़ते हैं तथा भोजन और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं।
- केल्प वन तटीय होते हैं और उन्हें उथले, अपेक्षाकृत साफ पानी की आवश्यकता होती है।
- वे अकशेरूकीय, मछलियों और अन्य शैवाल की सैकड़ों प्रजातियों को पानी के नीचे आवास प्रदान करते हैं और उनका महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य है।

केल्प वन का वितरण

- इनुइट द्वारा पूरे आर्कटिक क्षेत्र में केल्प वन देखे गए हैं। अकेले कैनेडियन आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के समुद्र तटों के 10 % का प्रतिनिधित्व करता है।
- वे गंभीर परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं। ठंडे पानी की इन प्रजातियों के पास ठंड के तापमान और लंबे समय तक अंधेरे से बचने और यहाँ तक कि समुद्री बर्फ के नीचे बढ़ने के लिए विशेष रणनीतियां होती हैं।
- ठंडे, पोषक तत्वों से भरपूर पानी वाले क्षेत्रों में, वे पृथ्वी पर किसी भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादन की कुछ उच्चतम दरों को प्राप्त कर सकते हैं।

स्रोत- डाउन टू अर्थ

हरित भारत मिशन

चर्चा में क्यों ?

- हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार भारत हरित भारत मिशन में निर्धारित वृक्षों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्यों में पिछड़ रहा है।

ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में:

- नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया (GIM) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना- 2008 (NAPCC) के तहत 8 मिशनों में से एक है।
- GIM, 2014 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लाया गया था।
- **उद्देश्य:** अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन का जवाब देना, जो मदद करेगा:
- कार्बन सिंक को बढ़ाने में ।
- बदलती जलवायु के लिए संवेदनशील प्रजातियों/पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूलन में।
- वन-आश्रित समुदायों के अनुकूलन में।
- 5 मिलियन हेक्टेयर वन/गैर-वन भूमि पर वन/वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करने में।
- जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले लगभग 30 लाख परिवारों की वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करने में।
- वर्ष 2020 में वार्षिक CO_2 पृथक्करण में 50 से 60 मिलियन टन की वृद्धि हुई।
- मिशन के तहत विभिन्न वन प्रकारों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए स्पष्ट लक्ष्य शामिल हैं।
- **ग्रीन इंडिया मिशन** के तहत गतिविधियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NPA) के साथ मिलकर लागू किया जाएगा।

स्रोत- द हिन्दू

अहोबिलम मठ मंदिर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में SC ने अहोबिलम मठ मंदिर पर आंध्र सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।

प्रमुख बिंदु

- यहाँ 2019 में एक कार्यकारी अधिकारी के मंदिर में नियुक्त किए जाने के बाद विरोध शुरू हुआ। अहोबिलम मठ से जुड़े श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम के प्रशासन को अपने हाथों में लेने की आंध्र प्रदेश सरकार की योजना को राज्य उच्च न्यायालय में विफल कर दिया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील पर कोर्ट ने इंकार कर दिया।

- उच्च न्यायालय के अनुसार, केवल अहोबिलम मठ के प्रमुख ही मंदिर के प्रशासन के प्रभारी हो सकते हैं, न कि धार्मिक बंदोबस्ती और धर्मार्थ संस्थान अधिनियम, 1987 के तहत राज्य बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त द्वारा नियुक्त कार्यकारी अधिकारी।

सरकार का तर्क

- सरकार के अनुसार पूर्व में भी मंदिर में कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी, परंतु कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला । मार्च, 2019 में एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद ही विरोध क्यों ?
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी –वर्तमान में मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने की मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।

श्री अहोबिला मठ

- श्री अहोबिला मठ (जिसे श्री अहोबिला मातम भी कहा जाता है) एक वडकलाई श्री वैष्णव मठ है जो वेदांत देशिक की वडकलाई परंपरा के बाद भारत के क्षेत्रों के अहोबिलम में 1400 कार्यालयों के आसपास स्थापित किया गया था।
- इसका श्रेय श्री आदिवन सातकोपा स्वामी (मूल रूप से श्रीनिवासाचार्य के नाम से जाना जाता है) को दिया जाता है।
- श्री अहोबिलम मठ परम्परा श्री लक्ष्मी स्वामी अहोबिलम देवस्थानम से जुड़ी हुई है। सामान्य धार्मिक प्रथाओं और प्रशासन में भागीदारी के कारण अहोबिलम मठ के साथ", यह "अहोबिलम मठ का अनिवार्य रूप से एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है"।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669